RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INSP
Institut national du service public

Concours d'entrée 2025

Voie Orient

Concours externe

Section : Asie méridionale et Extrême-Orient

Langue : Hindi

5ème épreuve d'admissibilité

Une épreuve consistant en des réponses courtes, dans la langue choisie au moment de l'inscription, à des questions à partir d'un dossier dans cette même langue permettant d'apprécier les connaissances linguistiques sur les thèmes économiques, culturels, sociaux de la section géographique choisie et l'aptitude à formuler des réponses complexes.

L'usage du dictionnaire est autorisé pour cette seule épreuve en arabe littéral, chinois, haoussa, hébreu, hindi, japonais, mandingue, persan, peul, swahili, turc et wolof. Pour ces langues, tous types de dictionnaires (à l'exclusion des dictionnaires électroniques) de la langue de l'épreuve vers le français, vers l'anglais ou vers une langue tierce sont autorisés, et vice versa. Les candidats utilisant un dictionnaire de langue de l'épreuve vers une autre langue que le français et l'anglais peuvent utiliser un dictionnaire de cette langue tierce vers le français et l'anglais. Sont, en outre, autorisés les dictionnaires rédigés exclusivement dans la langue de l'épreuve. Les dictionnaires peuvent faire l'objet de contrôles durant les épreuves. Ils ne peuvent être ni annotés, ni prêtés, ni échangés entre candidats durant l'épreuve.

Toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.

Durée : 3 heures – coefficient 3

Sujet

Question n°1 : भारत की « नेबरहुड फ़र्स्ट » नीति में क्या-क्या चुनौतियां हैं ?

Question n°2 : क्या भारत « ग्लोबल साउथ » का नेता बनना चाहता है ?

Question n°3 : क्या भारत और चीन संबंध सामान्य हो सकते हैं ?

क्या पुराने गिले शिकवे छोड़कर मालदीव और भारत फिर से क़रीब आ रहे हैं?

12 अगस्त 2024

भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर की मालदीव की तीन दिनों की यात्रा समाप्त हो गई है.

मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू की चीन से नज़दीकी ज़ाहिर होने के बाद यह भारत के किसी बड़े मंत्री की पहली मालदीव यात्रा थी.

भारत और मालदीव के बीच इसी साल की शुरुआत में मालदीव और लक्षद्वीप की तुलना के नाम पर बड़ा विवाद भी हुआ था. यह विवाद पीएम मोदी की एक तस्वीर पर मालदीव के मंत्रियों की टिप्पणी के बाद शुरू हुआ था.

एस जयशंकर ने अपनी इस यात्रा में मालदीव में यूपीआई से पेमेंट की सुविधा शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है.

इसके अलावा दोनों देशों के बीच आपसी संबंध को मज़बूत करने के लिए कई मुद्दों पर बातचीत हुई है.

राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू ने क्या कहा

विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाक़ात के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने एक्स पर पोस्ट किया है.

मुइज़्ज़ू ने लिखा है कि मालदीव के 28 द्वीपों में पानी और नाले से जुड़ी परियोजनाओं को आधिकारिक तौर पर सौंपे जाने के मौक़े पर डॉक्टर एस जयशंकर से मिलकर ख़ुशी हुई.

उन्होंने लिखा है, "हमेशा मालदीव की मदद करने के लिए मैं भारत सरकार और ख़ासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता हूं."

उन्होंने कहा है कि हमारी साझेदारी से दोनों देशों के बीच सुरक्षा, विकास और सांस्कृतिक संबंध और मज़बूत होंगे. हम इस क्षेत्र में ज़्यादा समृद्ध भविष्य का निर्माण करेंगे.

मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने अपने सोशल मीडिया पर एस जयशंकर के साथ मुलाक़ात की कुछ तस्वीरें भी पोस्ट की हैं.

ख़बरों के मुताबिक़ मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने भारत को अपने सबसे क़रीबी सहयोगियों में से एक बताया है.

वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी मालदीव के साथ संबंधों को ख़ास बताया है.

एस जयशंकर की इस यात्रा पर काफ़ी लोगों की नज़र थी.

चीन के सरकारी अख़बार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, "चीनी विशेषज्ञों ने रविवार को कहा है कि चीन मालदीव के साथ बहुत ख़ास संबंध या सहयोग की इच्छा नहीं रखता है, जबकि भारत इस इलाक़े में अपने प्रभुत्व के लिए चीन को एक डर के तौर पर पेश करता है."

एस जयशंकर की इस यात्रा पर मीडिया संस्थान 'सन' ने लिखा है कि एस जयशंकर की यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच आपसी संबंध बेहतर हुए हैं.

सन के मुताबिक़, "एस जयशंकर ने कहा है कि भारत 'नेबरहुड फ़र्स्ट' नीति के तहत द्वीपों से बने मालदीव की प्रगति को प्राथमिकता देगा."

एस जयशंकर की इस यात्रा पर पीएसएम न्यूज़ ने भारतीय विदेश मंत्री के बयान को छापा है. अख़बार के मुताबिक़ एस जयशंकर ने कहा है, "भारत मालदीव में मानव संसाधन और बुनियादी ढांचे के विकास को उच्च प्राथमिकता में रखता है."

वहीं एक अन्य मीडिया 'एडिशन' के मुताबिक़ जयशंकर ने अपनी इस यात्रा में सरकारी अधिकारियों के अलावा विपक्षी दल एमडीपी के अध्यक्ष और मालदीव के पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद से मुलाक़ात की.

अंग्रेज़ी अख़बार हिन्दुस्तान टाइम्स के मुताबिक़ अब्दुल्ला शाहिद ने भारत और मालदीव के बीच बीते समय में हुई घटना को लेकर खेद जताया है और भारत को लेकर मालदीव की मुइज़्ज़ू की नीति में आए बदलाव का स्वागत किया है.

विवाद कैसे शुरू हुआ था

इसी साल 4 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप की तस्वीरें शेयर कर लोगों ने वहाँ सैर सपाटे के लिए पहुँचने की अपील की थी.

इस अपील के बाद मालदीव के कुछ मंत्रियों की मोदी और भारत विरोधी टिप्पणी की थी. इससे दोनों देशों के बीच एक नया विवाद पैदा खड़ा हो गया था.

हालांकि मालदीव सरकार ने मामले को ठंडा करने के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मंत्रियों को निलंबित कर दिया और कहा कि इस तरह के बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारत में मालदीव के हाई कमिश्नर इब्राहिम शाहिब को बुला कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सोशल मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी पर गंभीर चिंता जताई थी.

मोहम्मद मुइज़्ज़ू पिछले साल नवंबर में मालदीव के राष्ट्रपति बने थे, उन्हें चीन के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए जाना जाता रहा है.

मुइज़्ज़ू ने अपने चुनावी अभियान में उस समय की मालदीव सरकार पर आरोप लगाया था कि देश के नीतिगत फ़ैसलों में भारत के दख़ल से 'मालदीव की संप्रभुता और आज़ादी' कमज़ोर पड़ी है.

मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने अपने चुनाव अभियान में 'इंडिया आउट' यानी भारत को देश से बाहर करने का नारा दिया था. मुइज़्ज़ू चीन के साथ बेहतर रिश्तों के पक्षधर हैं.

मोहम्मद मुइज़्ज़ू राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहले 27 नवंबर को तुर्की के दौरे पर गए थे. फिर वो अपनी पत्नी के साथ चीन के दौरे पर भी गए थे.

एक हज़ार से अधिक द्वीपों वाले मालदीव की आबादी सिर्फ़ 5 लाख 57 हज़ार के आसपास है. लेकिन यह देश भारत और चीन दोनों के लिहाज़ से अहम है.

मालदीव और भारत के बीच रिश्ते काफ़ी अच्छे रहे हैं और कई मौक़ों पर भारत ने मालदीव की मदद भी की है. मालदीव के नए राष्ट्रपति अक्सर अपना पहला विदेश दौरा भारत का करते थे.

मुइज्ज़ू के राष्ट्रपति बनने और फिर भारत के साथ विवाद शुरू होने के बाद दोनों देशों के आपसी संबंध को लेकर सवाल भी खड़े हो गए थे. लेकिन भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की ताज़ा यात्रा दोनों देशों के आपसी संबंधों के लिहाज़ से अहम हो सकता है.

Source : https://www.bbc.com/hindi/articles/czrglmj4kjeo

श्रीलंकाई राष्ट्रपति दिसानायके की पहली भारत यात्रा, दोनों देशों के संबंधों को बढ़ावा का संदेश

नई दिल्ली: भू-राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव के दौर में भारत-श्रीलंका संबंधों में कई उतार-चढ़ाव आए हैं. विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके की 15-17 दिसंबर तक नई दिल्ली की राजकीय यात्रा की घोषणा की. श्रीलंका में हाल ही में संपन्न राष्ट्रपति और संसदीय चुनावों के बाद राष्ट्रपति दिसानायके की यह पहली द्विपक्षीय भारत यात्रा होगी. इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है.

यह ऐसे समय में हुआ है जब द्वीप राष्ट्र अभी भी 2022 में अपने सबसे खराब वित्तीय ऋण से उबर रहा है. श्रीलंका में चीन के बढ़ते प्रभाव और इस तथ्य को देखते हुए कि भारत यात्रा के बाद दिसानायका अगले महीने बीजिंग जाने के लिए तैयार हैं, यह यात्रा महत्वपूर्ण है. विशेषज्ञ दिसानायके की नई दिल्ली यात्रा के समय को महत्वपूर्ण मानते हैं.

पूर्व भारतीय राजनयिक और विदेश नीति टिप्पणीकार अशोक सज्जनहार ने ईटीवी भारत से कहा कि यह वास्तव में शुरुआती दिन हैं और श्रीलंका के विदेश संबंधों के विकसित होते करीब से देखना आवश्यक है. हालांकि, श्रीलंका के राष्ट्रपति द्वारा अपनी यात्रा के लिए भारत को पहला गंतव्य चुनने से जो महत्वपूर्ण संदेश दिया जा रहा है, उसे पहचानना महत्वपूर्ण है.

सज्जनहार ने कहा कहा,'उदाहरण के लिए जब नेता किसी खास गठबंधन के बारे में बात करना चाहते हैं, तो हम इसे नेपाल में देख सकते हैं. जहां के.पी. शर्मा - जो कई कार्यकालों तक सेवारत रहे हैं. पहले चीन का दौरा करते हैं. ये चीन के साथ संबंधों को मजबूत करने की इच्छा का संकेत देता है. इसी तरह जब मुइज़ू ने पदभार संभाला तो उनकी शुरुआती प्राथमिकताओं में तुर्की, यूएई और चीन शामिल थे. अंत में भारत तक पहुंचे. ये स्पष्ट संकेत देते हैं. श्रीलंका के राष्ट्रपति का संदेश स्पष्ट है. वे भारत के साथ मजबूत और सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं. यह साझेदारी एक आधारशिला है जिसे वे आगे बढ़ने के लिए बनाए रखना चाहते हैं.'

भारत-श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए इस यात्रा के महत्व के बारे में पूछे जाने पर सज्जनहार ने कहा, 'भारत का श्रीलंका के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता है. हम इसे व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते में अपग्रेड करने के तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं. यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अब एक बड़ा बाजार और अर्थव्यवस्था है.

वर्तमान में श्रीलंका की निर्यात क्षमता सीमित है. यह मुख्य रूप से कपड़ा, चाय और पर्यटन पर निर्भर है. कोविड के दौरान और श्रीलंका में समन्वित ईस्टर बम हमलों से इन क्षेत्रों को काफी नुकसान हुआ है. भारत के साथ व्यापार और आर्थिक जुड़ाव का विस्तार करके और निवेश साझेदारी बनाकर, श्रीलंका अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकता है. यह अपने निर्यात में विविधता ला सकता है और केवल कुछ वस्तुओं पर निर्भरता कम कर सकता है.'

अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति दिसानायके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आपसी हितों के द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे. वे भारत और श्रीलंका के बीच निवेश और वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में एक व्यापारिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे. इसके अलावा वे यात्रा के हिस्से के रूप में बोधगया भी जाएंगे.

इस बीच नई दिल्ली में रहने वाले विदेश और सुरक्षा नीति विश्लेषक श्रीपति नारायणन ने कहा, 'राष्ट्रपति की भारत यात्रा अपेक्षित थी, खासकर हाल ही में हुए चुनावों के कारण. राष्ट्रपति बनने के बाद उनका आगमन विलंबित हो गया, क्योंकि वे संसदीय चुनावों के होने का इंतजार कर रहे थे. अब जबकि चुनाव समाप्त हो चुके हैं, यह भारत के लिए सकारात्मक विकास है कि उन्होंने चीन जैसे अन्य देशों में जाने से पहले भारत का दौरा करने का फैसला किया. इससे पता चलता है कि भारत उनके लिए प्राथमिकता है. यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति ए.के.डी. जेवीपी से जुड़े हैं. इसका मतलब है जनता विमुक्ति पेरामुना है.

जेवीपी का इतिहास एक उग्रवादी समूह के रूप में रहा है जो भारत विरोधी रहा है. उनकी यात्रा का उद्देश्य यह दिखाना है कि वे लोगों के अपने राजनीतिक दल के प्रति दृष्टिकोण को बदल रहे हैं और लोग समय के साथ बदल सकते हैं. दिसानायके ने संसदीय चुनावों में निर्णायक जीत हासिल की, जिसमें रूढ़िवादी और गैर-रूढ़िवादी सिंहल, मुस्लिम और तमिल सहित कई अलग-अलग समूहों का समर्थन प्राप्त हुआ.

पारंपरिक पार्टियां जो इन समूहों का प्रतिनिधित्व करती थी, चुनावों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई. इसका मतलब है कि वे केवल एक समूह का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश भर के कई मतदाताओं की उम्मीदों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. यह जेवीपी के लिए एक

महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि इसने अपने सामान्य आधार से परे अपने समर्थन का विस्तार किया है. राष्ट्रपति अब पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं.

विश्लेषक ने कहा,'आर्थिक पक्ष पर वे इसलिए जीते क्योंकि कई राजनीतिक दलों ने समस्याओं का सामना किया है और लोगों का विश्वास खो दिया है. अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही है, और जनता को उम्मीद है कि यह नया नेता इसे सुधारने में मदद कर सकता है. श्रीलंका की विदेश नीति के बारे में इस यात्रा का मतलब भारत और चीन के साथ उसके संबंधों में कोई बड़ा बदलाव नहीं है. ऐतिहासिक रूप से 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में श्रीलंका भारत की ओर अधिक झुका था और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता था. चीन के साथ उनके संबंध ज्यादातर वाणिज्यिक जरूरतों के बारे में थे.'

इस यात्रा के दौरान चर्चा का एक मुख्य विषय श्रीलंका का ऋण संकट और उसकी चल रही आर्थिक सुधार है. चीन श्रीलंका का सबसे बड़ा ऋणदाता है. इसके पास उसके द्विपक्षीय ऋण का आधे से अधिक हिस्स

Source : https://www.etvbharat.com/hi/!bharat/srilankan-president-anura-dissanayake-maiden-visit-to-india-sends-out-a-strong-message-of-fostering-strong-and-positive-ties-with-its-neighbour-hindi-news-hin24121400483

तीसरा वॉयस ऑफ़ ग्लोबल साउथ समिट 2024

अगस्त 14, 2024

17 अगस्त 2024 को भारत तीसरे वॉयस ऑफ़ ग्लोबल साउथसमिट की मेज़बानी करेगा। यह अनोखी पहल भारत के प्रधानमंत्री श्री. नरेंद्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास' को विस्तार देने के नज़रिए और वसुधैव कुटुम्बम की भारतीय अवधारणा पर आधारित है। इसमें विभिन्न मुद्दों पर अपने नज़रिए और अपनी प्राथमिकताओं को एक मंच पर साझा करने के लिए ग्लोबल साउथ के देशों को एक साथ लाने की परिकल्पना की गई है।

2. भारत ने 12-13 जनवरी 2023 को पहला वॉयस ऑफ़ ग्लोबल साउथ समिट (वीओजीएसएस) और 17 नवंबर 2023 को दूसरा वॉयस ऑफ़ ग्लोबल साउथ समिट वर्चुअल प्रारूप में आयोजित किया था। दोनों ही पिछले संस्करणों में ग्लोबल साउथ के 100 से अधिक देशों की भागीदारी देखी गई थी। इन दोनों शिखर सम्मेलनों में विकासशील देशों के नेताओं के मिली इनपुट और फ़ीडबैक को बीते वर्ष भारत की अध्यक्षता में जी20 शिखर सम्मेलन के एजेंडे में, चर्चाओं के दौरान और जी20 नई दिल्ली के घोषणापत्र में भी उचित रूप से दर्शाया गया था।

3. "एक सतत भविष्य के लिए सशक्त ग्लोबल साउथ" के अपने व्यापक विषय के साथ तीसरा वीओजीएसएस पिछले शिखर सम्मेलनों के दौरान की गई उन कई जटिल चुनौतियों पर चर्चाओं को विस्तार देने के मंच के रूप में काम करेगा, जिनसे दुनिया प्रभावित हो रही है, जैसे- संघर्ष, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा संकट, जलवायु परिवर्तन - ये सभी विकासशील देशों को विषमतापूर्वक गंभीर रूप से प्रभावित कर रहे हैं। तीसरे ग्लोबल साउथ समिट में ग्लोबल साउथ के देश, ग्लोबल साउथ में विशेष कर विकास के क्षेत्रों में चुनौतियों, प्राथमिकताओं और समाधानों पर अपने विस्तृत विचार विमर्श जारी रखेंगे।

4. पिछले दो शिखर सम्मेलनों की भांति ही तीसरा वॉयस ऑफ़ ग्लोबल साउथ समिट (वीओजीएसएस) भी वर्चुअल प्रारूप में आयोजित किया जाएगा और इसमें नेताओं एवं मंत्रियों के सेशन की व्यवस्था की गई है। उद्घाटन सत्र देश के प्रमुख/सरकार के स्तर पर होगा और इसकी मेज़बानी प्रधानमंत्री श्री. नरेंद्र मोदी करेंगे। उद्घाटन सत्र का थीम इस शिखर सम्मेलन के व्यापक थीम के समान "एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ" ही है।

5. इसके अलावा, निम्नलिखित विषयों पर 10 मंत्रिस्तरीय सत्र भी होंगेः

i. "ग्लोबल साउथ के लिए एक आदर्श प्रतिमान की रूपरेखा तैयार करना" पर विदेश मंत्रियों का सत्र

ii. "वन वर्ल्ड- वन हेल्थ" पर स्वास्थ्य मंत्रियों का सत्र

iii. "बेहतर भविष्य के लिए युवाओं का जुड़ाव" पर यूथ मंत्रियों का सत्र

iv. "ग्लोबल साउथ के नज़रिए से विकास के लिए व्यापार" पर वाणिज्य/व्यापार मंत्रियों का सत्र

v. "विकास के लिए डीपीआई- ग्लोबल साउथ का नज़रिया" पर सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रियों का सत्र

vi. "ग्लोबल फ़ाइनैंस के लिए जन आधारित दृष्टिकोण" पर वित्त मंत्रियों का सत्र

vii. "ग्लोबल साउथ और ग्लोबल गवर्नेंस" पर विदेश मंत्रियों का दूसरा सत्र

viii. "सतत भविष्य के लिए सतत ऊर्जा समाधान" पर ऊर्जा मंत्रियों का सत्र

ix. "मानव संसाधन विकास को प्राथमिकता देनाः ग्लोबल साउथ का नज़रिया" पर शिक्षा मंत्रियों का सत्र

x. "प्रगति के रास्तेः जलवायु परिवर्तन के असर को घटाने पर ग्लोबल साउथ का नज़रिया" पर पर्यावरण मंत्रियों का सत्र

नई दिल्ली

Source : https://www.mea.gov.in/press-releases-hi.htm?dtl/38161/The+3rd+Voice+of+Global+South+Summit+2024

जयशंकर बोले- भारत-चीन सीमा पर 2 वजहों से समझौता:पहला- हम अड़े रहे, सेना डटी रही, कूटनीति काम आई, दूसरा- इन्फ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया

भारत-चीन के बीच LAC पर पेट्रोलिंग को लेकर समझौते पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत सरकार का अपनी बात पर अड़े रहना काम कर गया। आज हम जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, उसके दो कारण हैं।

पहला- हम अपनी बात से पीछे नहीं हटे यह केवल इसलिए संभव हो सका क्योंकि सेना देश की रक्षा के लिए हर मौके पर डटी रही और कूटनीति ने अपना काम किया।

दूसरा- पिछले एक दशक में हमने अपने बुनियादी ढांचे में भी सुधार किया है।

जयशंकर ने कहा- मुझे लगता है कि इन दो कारणों के चलते भारत-चीन सीमा विवाद पर पेट्रोलिंग का मुद्दा हल हो सका है। विदेश मंत्री ने यह बात शनिवार को पुणे के एक कार्यक्रम में कही।

चीन बॉर्डर पर सेना की पेट्रोलिंग को रोका जा रहा था। हम पिछले 2 सालों से इसी मुद्दे को हल करने की कोशिश में लगे थे। अब पेट्रोलिंग पर सहमति बन गई है जैसे पहले हुआ करती थी।

एस जयशंकर
विदेश मंत्री

जयशंकर ने ऐसा क्यों कहा...

दरअसल, भारत-चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में चार साल से सीमा विवाद को लेकर तनाव था। दो साल की लंबी बातचीत के बाद पिछले दिनों एक समझौता हुआ है। दोनों सेनाएं विवादित पॉइंट्स देपसांग और डेमचोक से पीछे हटेंगी।

18 अक्टूबर: देपसांग और डेमचोक से पीछे हटने की जानकारी सामने आई थी। इसमें बताया गया था कि यहां से दोनों सेनाएं अप्रैल 2020 से पहली की स्थिति में वापस लौटेंगी। साथ ही उन्हीं क्षेत्रों में गश्त करेंगी, जहां अप्रैल 2020 से पहले किया करती थीं। इसके अलावा कमांडर लेवल मीटिंग होती रहेगी

2020 में भारत-चीन के सैनिकों के बीच गलवान झड़प के बाद से देपसांग और डेमचोक में तनाव बना हुआ था। करीब 4 साल बाद 21 अक्टूबर को दोनों देशों के बीच नया पेट्रोलिंग समझौता हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया था कि इसका मकसद लद्दाख में गलवान जैसी झड़प रोकना और पहले जैसे हालात बनाना है।

25 अक्टूबर: भारत और चीन की सेनाएं शुक्रवार, 25 अक्टूबर से पूर्वी लद्दाख सीमा से पीछे हटना शुरू हो गई हैं। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक पूर्वी लद्दाख के डेमचोक और देपसांग पॉइंट में दोनों सेनाओं ने अपने अस्थायी टेंट और शेड हटा लिए हैं। गाड़ियां और मिलिट्री उपकरण भी पीछे ले जाए जा रहे हैं।

आर्मी के सूत्रों के मुताबिक 28 और 29 अक्टूबर तक दोनों देश देपसांग और डेमचोक से अपनी- अपनी सेनाएं पूरी तरह हटा लेंगे। पेट्रोलिंग के लिए सीमित सैनिकों की संख्या तय की गई है। ये संख्या कितनी है, इसकी अभी जानकारी सामने नहीं आई है।

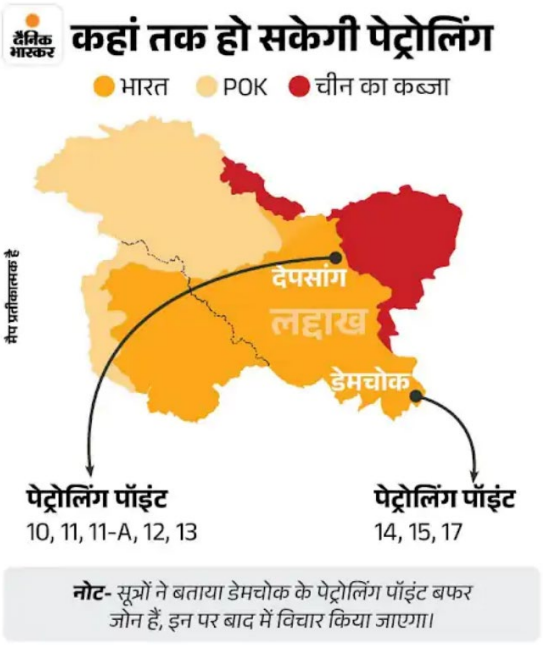

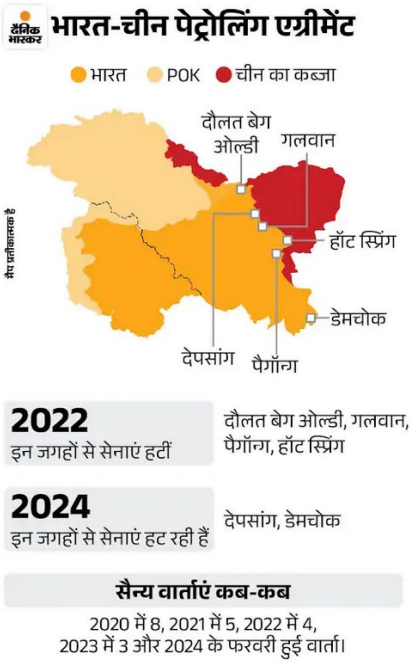

3 पॉइंट में भारत-चीन का पेट्रोलिंग समझौता

1. PM मोदी की ब्रिक्स यात्रा के पहले समझौता फाइनल हुआ। ब्रिक्स में मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई थी। मोदी ने यहां कहा था कि शांति कायम रखना हर हाल में जरूरी है।

2. पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) पर अप्रैल 2020 की स्थिति बहाल करने के लिए चीन और भारत राजी हुए। यानी अब चीन की आर्मी उन इलाकों से हटेगी, जहां उसने अतिक्रमण किया था।

3. भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विक्रम मिस्री ने बताया था कि भारत-चीन के सीमावर्ती इलाकों में पेट्रोलिंग के साथ 2020 के बाद उठे मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रस्ताव तैयार हुआ है। इस पर दोनों देश कदम उठाएंगे।

गलवान में 15 जून 2020 को झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए

15 जून 2020 को चीन ने ईस्टर्न लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों में एक्सरसाइज के बहाने सैनिकों को जमा किया था। इसके बाद कई जगह पर घुसपैठ की घटनाएं हुई थीं।

भारत सरकार ने भी इस इलाके में चीन के बराबर संख्या में सैनिक तैनात कर दिए थे। हालात इतने खराब हो गए कि LAC पर गोलियां चलीं।

इसी दौरान 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। बाद में भारत ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया था। इसमें करीब 60 चीनी जवान मारे गए थे।

Source : https://www.bhaskar.com/national/news/jaishankar-said-agreement-on-india-china-border-due-to-2-reasons-133867519.html